नहीं मान रहे धंधेबाज अब होगी कार्रवाई

संवाददाता ■ पटना

आवासीय कॉलोनियों से व्यावसायिक गतिविधियां और अवैध निर्माण हटाने के लिए नगर निगम द्वारा दिया गया 72 घंटा का समय सोमवार की शाम खत्म हो गया. अब निगम प्रशासन इन आवासीय कॉलोनियों में कभी भी अवैध निर्माण तोड़ने और व्यावसायिक गतिविधियों को सील करने के लिए अभियान चला सकता है. निगम ने इसके लिए टीम गठित कर लिया है. नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने बताया कि पहला अभियान बोरिंग रोड पर चलेगा. 31 जुलाई से बोरिंग रोड के किनारे पटना इंप्रुवमेंट ट्रस्ट के भूखंड पर चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठान को चिह्नित करने के साथ साथ सील किया जायेगा. अभियान के दौरासन मजिस्ट्रेट भी रहेंगे.

गौरतलब है कि पीआरडीए ने आवासीय कॉलोनी के रूप में राजेंद्र नगर, एसके पुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी व कृष्ण नगर को बसाया, लेकिन आवंटियों ने बहुमंजिले इमारतें बना लीं और व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करना शुरू कर दिया. वर्तमान में नगर आयुक्त ने आवंटन के लीज-डीड की शर्तों के अनुरूप व्यावसायिक गतिविधियां खत्म करने का आदेश दिया है. इसके लिए 72 घंटा का समय दिया था, जो खत्म हो गया है.

अल्टीमेटम की अवधि समाप्त, 31 से चलेगा व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने का अभियान

हाइकोर्ट से भी राहत नहीं

पटना ■ हाइकोर्ट ने आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के पटना नगर निगम के आदेश को सही ठहराया है. न्यायमूर्ति जेएन सिंह के एकलपीठ ने एसके पुरी के आरके जैन व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. नगर निगम के वकील एचएस हिमकर ने कहा कि आवासीय कॉलोनियों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों से यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है. इस दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

बहुमंजिली इमारतों के निर्माण पर रोक जारी

पटना ■ हाइकोर्ट ने गंगा किनारे बन रही बहुमंजिली इमारतों के निर्माण पर रोक को जारी रखा है. अपर महाधिवक्ता ललित किशोर के अनुरोध पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को निर्धारित किया है. सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट से तीन महीने की मोहलत मांगी थी, जिसे उसने मंजूर कर लिया और तब तक अंतरिम आदेश जारी रहने की बात कही. पूर्व की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश रेखा एम दोशित के खंडपीठ ने तत्काल निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी.

एक छत और चार स्कूल

आपने बिना भवन व शिक्षकों के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के कई किस्से सुने होंगे. संभव हो कि आपके गांव व मुहल्ले में भी ऐसे स्कूल दिख जाएं. लेकिन, क्या आपने कभी यह सुना कि एक छत के नीचे चार सरकारी स्कूल चलाये जा रहे हैं. नामुमकिन-सा लगनेवाली यह बात सोलह आने सच है. **पूजा सिंह** की रिपोर्ट.

संवाददाता ■ पटना

राजधानी के नाला रोड में एक छत के नीचे दो शिफ्टों में आज चार सरकारी स्कूल चल रहे हैं. इनके नाम हैं- बालक मध्य विद्यालय, बापू स्मारक कन्या मध्य विद्यालय, नवीन कन्या मध्य विद्यालय व प्राथमिक मध्य विद्यालय. इनमें नवीन कन्या मध्य विद्यालय व प्राथमिक मध्य विद्यालय सुबह की शिफ्ट यानी साढ़े सात से साढ़े 11 बजे तक चलते हैं. शेष दो स्कूल पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे से शाम साढ़े चार बजे तक चलते हैं. आश्चर्य की बात यह है कि बापू स्मारक कन्या मध्य विद्यालय के इस भवन की नींव वर्ष 1997 में पड़ी थी, लेकिन अब तक न तो शिक्षा विभाग और न ही जिला प्रशासन की ही नजर इस पर पड़ी.

एक साथ चल रहे ये स्कूल
- बालक मध्य विद्यालय
- बापू स्मारक कन्या मध्य विद्या
- नवीन कन्या मध्य विद्यालय
- प्राथमिक मध्य विद्यालय.

एक कमरे में 90 छात्र

बालक मध्य विद्यालय में 90 छात्र नामांकित हैं. इनके लिए एक कमरा है. इसी कमरे में नवीन कन्या मध्य विद्यालय भी चलता है. इसमें भी 102 बच्चे हैं. वहीं, बापू स्मारक कन्या मध्य विद्यालय में 250 बच्चे हैं, जिनके के लिए पांच कमरे उपलब्ध हैं. इन्हीं कमरों में प्राथमिक मध्य विद्यालय (40 छात्र) भी चलता है. हालांकि, सभी कमरों का इस्तेमाल प्राचार्य व शिक्षक नहीं कर पाते हैं. इनमें एक-दो कमरे अक्सर बंद रहते हैं. एक कमरे में ही बालक मध्य विद्यालय की प्राचार्या का ऑफिस व जरूरी कागजातों को रखने के लिए ट्रंक व अलमीरा रखा गया है.

■ एक कमरे में दो स्कूलों की पढ़ाई

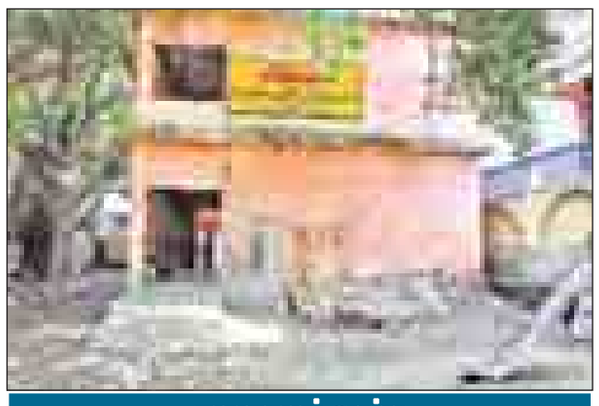

समस्याएं अनंत
- छोटा कैंपस, शौचालय नहीं
- खेलकूद के लिए व्यवस्था नहीं
- पेयजल की स्थिति ठीक नहीं है
- बच्चों के लिए बैठने की समस्या
- कक्षा व ऑफिस एक कमरे में
- रात को असामाजिक तत्वों व अपराधियों का होता है बसेरा
- प्रशासनिक व्यवस्था नहीं
- मनचलों की हरकतों से छात्राएं परेशान

शौचालय की व्यवस्था नहीं

परिसर में एक शौचालय है, लेकिन उसकी हालत सही नहीं होने के कारण उसे बंद कर दिया गया है. एक चापाकल खराब है. पेयजल के लिए लगाये गये नल पर आसपास के लोगों ने कब्जा कर रखा है. वे यहां नहाने व कपड़े धोने का भी काम करते हैं.

व्यवस्था ठीक नहीं है. इसकी जानकारी डीओ ऑफिस को लिखित रूप में दी जा चुकी है. इन स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ाई होती है. एक कमरा है. इसका उपयोग या तो ऑफिस के लिए किया जा सकता है या फिर क्लास रूम कम गोदाम के लिए.
उषा रानी, प्राचार्या, बालक मध्य विद्या

अच्छा वातावरण मिले, तो नामांकन में वृद्धि हो सकती है. यहां लड़कियों सहित शिक्षिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना आम है. इससे परेशानी होती है. इसके लिए पुलिस व जिला प्रशासन को शिकायत की गयी, पर अभी तक ठोस पहल नहीं हुई.
निर्मला प्राचार्या, बापू स्मारक कन्या मध्य विद्या

जमीन के अभाव में एक ही कैंपस में चार स्कूल रहे हैं. महेंदू अंचल के नवीन कन्या मध्य विद्यालय व बालक मध्य विद्यालय को बांकीपुर अंचल में शिफ्ट किया गया है. जमीन की तलाश हो रही है. ताकि, स्कूलों को जल्द भवन उपलब्ध कराया जा सके.
राजश्री, बीइओ, महेंदू अंचल

जदयू का किसी दल से गंठबंधन नहीं : नीतीश

संवाददाता ■ पटना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अभी किसी भी पार्टी से जदयू का गंठबंधन नहीं है. कांग्रेस से कोई बात नहीं चल रही है. विधानसभा स्थित अपने कक्ष में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने किसी भी दल या गंठबंधन के साथ होने से इनकार किया.

अलग नहीं होते, तो दोषी होते

भाजपा से अलग होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस मामले में स्थिति तो साफ थी. सब कुछ सामने लिखा हुआ था. हम निर्णय नहीं लेते, तो दोषी होते. संबंध समाप्त करने को लेकर तकनीकी पेचीदगी में फंसने का समय नहीं था. इसको लेकर भी भाजपा नेताओं को बुलाया, वे नहीं आये. कैबिनेट की मीटिंग की कि आखिर अलग होने का रास्ता किस तरह का हो. उसमें भी वे नहीं आये. आखिर हम क्या करते? जो परिस्थिति आ गयी थी, उसमें हम मुगालते में रहते? अपना समय क्यों बरबाद करते? हमने अपने संबोधन में धर्मनिरपेक्ष छविवाले मुख्यमंत्री की बात की थी. मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया था. वे खुद ही जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, उसे भी धर्मनिरपेक्ष नहीं मानते हैं. उन्होंने कहा कि छह माह पहले कुछ और बात थी. तब बिहार में बाहरी हस्तक्षेप नहीं था. 2005 का पहला व दूसरा विधानसभा चुनाव और 2009 के लोकसभा चुनाव के समय बात हुई थी. कांग्रेस के विरोध में लहर थी. कांग्रेस के विरोध में सभी दल एक साथ भारत बंद में शामिल थे. अगले चुनाव के लिए और अधिक सहयोगियों की जरूरत थी. बड़ी पार्टी की जिम्मेवारी थी कि और अधिक सहयोगियों की तलाश करे. पर, जो व्यक्ति 1994 से कभी सिद्धांतों को लेकर समझौता नहीं किया, वह एक सरकार के लिए परवाह करेगा. आगे जो होगा देखा जायेगा. उन्होंने भाजपा का नाम लिये बगैर कहा कि वह पानी का बुलबुला है. कमजोर आदमी चीखता है. आखिर उनके सामने मुद्दा क्या है? अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने क्या कहा? बिहार मॉडल की ही तो प्रशंसा की. उसमें भाजपा भी भागीदार रही है. वे अब उनका भी विरोध कर रहे हैं.

पटना अपडेट

अब भाजपा में रामकिशोर के बागी बोल

पटना ■ भाजपा के प्रवक्ता व पूर्व विधान परिषद सदस्य राम किशोर सिंह ने कहा है कि गुजरात के विकास में केशुभाई का भी हाथ है. राज्य का विकास 25 वर्षों के भाजपा शासनकाल का परिणाम है. उन्होंने कहा कि किसी एक राज्य के विकास मॉडल को देश का विकास मॉडल नहीं बनाया जा सकता. सभी राज्यों का विकास अपनी भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितियों में हुआ है. उक्त जानकारी वे विधानसभा परिसर में पत्रकारों को दे रहे थे. राम किशोर सिंह का बयान उस समय आया है जब बिहार भाजपा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विकास मॉडल की तारीफ करती थक नहीं रही है. अमरनाथ गामी के बाद रामकिशोर सिंह की इस बात से भाजपा को परेशानी हो सकती है. वे पार्टी के प्रवक्ता भी हैं. भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाये गये विश्वासघात के आरोपों पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भी तो विश्वासघात की बात कर रहे हैं.

अपराधियों ने महिला से छीनी चेन

पटना ■ सोमवारी की पूजा कर घर लौट रही रंचना सिन्हा के गले से सोने की चेन अपराधियों ने छीन ली. घटना शास्त्रीनगर थाने के बोर्ड कॉलोनी में हुई. घटना की सूचना वरीय अधिकारियों को नहीं देने के आरोप में शास्त्री नगर थाने के अवर निरीक्षक मुनीर आलम को एसएसपी ने निलंबित कर दिया गया है. थानाध्यक्ष आइसी विद्या शर्मा से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है. रंचना बेतिया के एमवीआइ राकेश कुमार सिन्हा की पत्नी हैं. रंचना पश्चिमी पटेल नगर में रहती हैं. गुरुवार को भी बाइक सवार अपराधियों ने पूर्व मंत्री नवल किशोर शाही की पुत्र वधू कृष्णा शाही से सोने की चेन लूट ली थी. बताया गया कि सोमवार की सुबह साढ़े नौ बजे रंचना सिन्हा शिव मंदिर में पूजा करने के बाद पैदल अपने घर लौट रही थीं. जैसे ही वे बोर्ड कॉलोनी के समीप पहुंचीं. उसी समय काले रंग की बाइक से दो अपराधी आये. पीछे बैठा अपराधी उनके गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गया. बाद में शोर मचाने पर लोग घटनास्थल पर जुटे. पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया.

रूपम पाठक की याचिका पर अंतरिम रोक

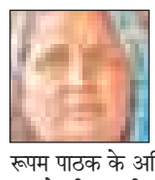

पटना ■ सुप्रीम कोर्ट ने रूपम पाठक की अपील याचिका पर पटना हाइकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एसके पटनायक व जगदीश सिंह केहर के खंडपीठ में सुनवाई हुई. कोर्ट ने हाइकोर्ट में दायर अपील याचिका की सुनवाई पर रोक लगायी. कोर्ट ने रूपम पाठक के अधिवक्ता को काउंटर हलफनामा दायर करने को कहा. इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी. भाजपा विधायक राजकिशोर केसरी हत्याकांड में रूपम पाठक को आजीवन कारावास की सजा मिली है. फिलहाल वह जमानत पर हैं. उन्होंने हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर की है. इसके खिलाफ केसरी के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

भाजपा व राजद में सांठगांठ : नीरज

पटना ■ जदयू नेता व विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा कि भाजपा व राजद में सांठगांठ है. दोनों दल मिल कर सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं. जिन विषयों पर विधान परिषद की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा हो गयी, विषय का चयन चर्चा के लिए हो गया, उसके बावजूद कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए सदन की कार्यवाही को बाधित करना लोकतंत्र की परंपरा के विरुद्ध है. उन्होंने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भाजपा, राजद व सीपीआइ सहित अन्य दलों के सदस्य भी मौजूद थे. सिर्फ राजनीति करने के लिए हंगामा हो रहा है.

सीबी सिंह एआरटीइइ के राज्य सचिव बने

पटना ■ पटना दूरदर्शन के सीबी सिंह अभय एसोसिएशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन इंजीनियरिंग इंप्लाइज (एआरटीइइ) के राज्य सचिव निर्वाचित हुए हैं. नयी दिल्ली में हुई मतगणना में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को आठ मतों से हरा दिया. नालंदा जिले के रहुई थाने के पितौझिया गांव के निवासी श्री सिंह तीन वर्षों से अधिक समय से पटना दूरदर्शन में इए के पद पर कार्यरत हैं. एआरटीइइ के राज्य सचिव निर्वाचित होने पर उन्हें पटना दूरदर्शन व रेडियो के कर्मियों ने बधाई दी है.

विप में हंगामा, कोई काम नहीं

संवाददाता ■ पटना

मशरक कांड पर हंगामे व नारेबाजी के कारण विधान परिषद की कार्यवाही सोमवार को पूरे दिन बाधित रही. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भाजपा व राजद द्वारा पेश किये गये अलग-अलग कार्यस्थगन प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया. भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष सुशील कुमार मोदी ने बोधगया मंदिर पर आतंकी हमला मामले पर, वहीं राजद की ओर से प्रो गुलाम गौस ने मिड डे मील कांड पर चर्चा कराने की मांग को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था. प्रस्तावों के अस्वीकृत होने पर भाजपा व राजद सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी. हंगामे को देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी. दोपहर ढाई बजे जैसे ही विप की दूसरी पाली की कार्यवाही शुरू हुई और सभापति आसन पर बैठे ही थे कि भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के बयान के बाद पार्टी के सभी सदस्य वेल में आ गये. सबों के हाथ में बोधगया में आतंकवादी हमले पर मुख्यमंत्री इस्तीफा दो की तख्ती थी . भाजपा के गिरिराज सिंह, नरेंद्र प्रसाद सिंह, मंगल पांडे, किरण घई व अन्य सदस्य तथा राजद के प्रो नवल किशोर यादव, डॉ तनवीर हसन सहित अन्य सदस्य वेल में पहुंच गये. आसन के समक्ष हाथों में पोस्टर लेकर भाजपा सदस्य बोधगया ब्लास्ट पर चर्चा की मांग करने लगे. राजद सदस्य मिड डे मिल पर दोषी सीएम इस्तीफा दो की तख्ती लेकर नारे लगा रहे थे. भाजपा व राजद सदस्यों के वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी से जदयू सदस्य भी अपनी सीट पर खड़े होकर विपक्ष के खिलाफ नारे लगाने लगे. लोकतंत्र पर हमला नहीं चलेगा और विपक्ष की क्या पहचान, राजद-भाजपा एक समान का नारा लगाते हुए जदयू के नीरज कुमार सहित अन्य सदस्यों ने विपक्षी सदस्यों पर निशाना साधा. हो-हंगामे के चंद मिनटों बाद ही सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी.

कार्यस्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत

विस के द्वार पर प्रदर्शन करते राजद के सदस्य.

विधान परिषद में मिड डे मील पर चर्चा आज

कार्यस्थगन प्रस्तावों को अस्वीकृत करते हुए सभापति ने कहा कि मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद मिड डे मील पर विशेष चर्चा होगी. विधान परिषद की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय किया गया है. ऐसे में सदन की कार्यवाही बाधित करना ठीक नहीं है.

प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पेश

विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच प्रभारी वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी रखी. हालांकि, इस पर चर्चा नहीं हो सकी. प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी 2013-14 में 11107.68 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित की गयी है. इसके तहत गैर योजना में 176.29 करोड़, राज्य योजना में 10881.17 करोड़, केंद्रीय योजनागत योजना में 7.86 करोड़, केंद्र प्रायोजित योजना में 40.35 करोड़ व प्रभूत में 2.01 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

मशरक कांड में प्रशासन संवेदनहीन : नंदकिशोर

पटना ■ मशरक के गंडामन स्कूल में मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत के मामले पर सोमवार को विधानसभा में हुई विशेष चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर आरोपों की बौछार की. पक्षविपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. विरोधी दल के नेता नंद किशोर यादव ने कहा कि यह घटना प्रशासन की संवेदनहीनता का परिणाम है. यह घटना अचानक नहीं घटी. दो जुलाई को काजीपुर सहित अन्य विद्यालयों में भी खराब भोजन की शिकायत मिली थी. राज्य निदेशालय की रिपोर्ट में भी खराब स्थिति की जानकारी मिल रही है. राज्य में मिड डे मिल के मामले में छपरा का स्थान 36 वां है. जब वहां पर एक-दो बजे के बीच घटना हुई, तो आनन-फानन में बीमार बच्चों को सदर अस्पताल लाया गया. मशरक अस्पताल में कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी. छपरा में भी दो घंटे तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका. मशरक से पांच-छह किमी पर घटना हुई, तो प्रशासन नहीं जगा. चार-पांच बजे डीएम मतदान केंद्रों को लेकर बैठक कर रहे थे. उसने कोई सक्रियता नहीं दिखायी. अब तक वहां कोई मंत्री नहीं गया है. अगर विरोधी दल साजिश करते, तो पदाधिकारी वहां कैसे पहुंचते.

चर्चा के दौरान प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री विजेंद्र यादव ने उन्हें टोका कि पीएचसी में क्या नहीं था. जवाब में नंद किशोर यादव ने कहा कि सत्ता मद में बेचैन हो गये हैं. जो बच्चे मरे हैं, वे कॉरपोरेट घराने के बच्चे नहीं हैं. मुख्यमंत्री पीएमसीएच में बच्चों को देखने इसलिए नहीं गये कि उनके पैर की अंगुली में चोट है, पर वह सरकार बचाने के लिए विधानसभा में पहुंच गये हैं. पीएमसीएच में विधानसभा से कम सीढ़ियां चढ़नी पड़तीं. सरकार बताये कि किस रिपोर्ट में यह बात आयी है कि प्रधानाध्यापिका के पति की राशन की दुकान है. सत्ता पक्ष द्वारा यह पूछे जाने पर आप रहते तो क्या करते? जवाब में नंद किशोर यादव ने बताया कि छठ के मौके पर हुए हादसे के दौरान हमने तीन घंटे में सभी व्यवस्था कर दी थी. नीतीश कुमार ने रेल मंत्री रहते हुए एक लाइनमैन की गलती से हुए रेल हादसे पर इस्तीफा दिया था. वह 23 बच्चों की मौत पर जनता से मांफी मांगते, जनता माफ कर देती. उन्होंने कहा कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात. अब मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सदानंद बाबू के साथ है. याद करे 1974 में क्या हुआ था.

सात साल में पहली बार कार्यस्थगन मंजूर : भोजनावकाश के पूर्व राजद नेता अब्दुलबारी सिद्दीकी के कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने ढाई बजे इस पर चर्चा कराने का समय निर्धारित किया. चर्चा की शुरुआत करते हुए सिद्दीकी ने कहा कि पिछले साढ़े सात वर्षों में पहली बार कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया गया. उन्होंने कहा कि मशरक कांड पर पहली राजनीति शिक्षा मंत्री ने की. उन्होंने प्रधानाध्यापिका की जाति व उसके पति का तार इससे जोड़ा. इसे कोई सभ्य समाज माफ नहीं कर सकता. मुख्यमंत्री को अगर बच्चों की मौत का दुःख होता, तो ऐसे मंत्री को सबसे पहले हटाते.

सदानंद सिंह के भाषण के समय हंगामा : कांग्रेस नेता सदानंद सिंह को अपनी बात रखने का मौका मिला,उसी समय भाजपा नेता अश्विनी कुमार चौबे समेत भाजपा के सभी विधायक वेल में आ गये. अश्विनी चौबे व प्रमोद कुमार सिंह आसन के पास पहुंच गये और जदयू विधायक मंजीत सिंह से मांफी मांगने की मांग करने लगे. श्री सिंह ने कहा कि जब बच्चे छपरा लाये गये, उस समय अस्पताल में दवा नहीं थी.चर्चा में जदयू के मंजीत कुमार सिंह, राजेश सिंह व कृष्ण कुमार, सीपीआइ के अवधेश कुमार राय, निर्दलीय पवन कुमार जायसवाल और भाजपा के जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, जनक सिंह व विनय कुमार ने भी भाग लिया.

विस में चर्चा के दौरान विपक्ष ने लगाये कई आरोप, नोकझोंक

जनता के मुद्दों को गंभीरता से उठाएं विधायक: सिद्दीकी

पटना ■ विधानमंडल के अंदर राजद एकला चलो की नीति पर चलेगा. मिड डे मील प्रकरण पर विधानसभाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी द्वारा विधायक दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, मुख्य सचेतक सम्राट चौधरी व प्रो अब्दुल गफूर द्वारा लाये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव को मंजूर किया जाना पार्टी की एक बड़ी रणनीतिक जीत हुई है. इसका संदेश पूरे राज्य में जायेगा. पार्टी विधायक जनहित से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से उठाएं. राज्य के अंदर हाल के दिनों में घटित घटनाओं पर विधानमंडल के अंदर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है. इसके लिए मॉनसून सत्र को बढ़ाया जाना चाहिए. ये बातें राजद विधायक दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सोमवार को पार्टी विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहीं. बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 23 बच्चों की मौत पर सरकार घटिया राजनीति कर रही है. विधानसभा स्थित चैंबर में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के अंदर नहीं आये. जब उनके द्वारा यह सवाल उठाया गया, तब वे आये. यह उनकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है. पार्टी के विधायकों को सदन के अंदर व बाहर एकजुटता बनाये रखने की जरूरत है. प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि अभी तो भाजपा से सेमीफाइनल में आज विजयी हुए हैं. अगले साल होनेवाले लोकसभा चुनाव में जदयू के साथ होनेवाले फाइनल मैच में बड़ी जीत होगी. उन्होंने कहा कि सदस्य ध्यानाकर्षण के माध्यम से जनहित के मुद्दों को उठाएं. मुख्य सचेतक सम्राट चौधरी ने कहा कि पार्टी के विधायकों को सदन के अंदर सजग रहने की जरूरत है.

आइआइटी ने सौर ऊर्जा उत्पादन में दिखायी राह

उपलब्धि

■ विवेक मिश्रा

पटना

बिहार की विकास गाथा में जब भी ऊर्जा की बात आती है तो शुरुआत अंधेरे से होती है. सबने मान भी लिया है कि मौजूदा ऊर्जा व्यवस्था के साधन सीमित
- अपनी जरूरत के साथ समय समय पर बिहार सरकार को भी करता है बिजली सप्लाइ

हैं. इसलिए इसके विकल्प की तलाश शुरू हुई. धूप और हवा में अपार संभावनाएं दिखीं. धूप से सौर ऊर्जा और हवा के जरिये पवन ऊर्जा जैसी चीजों पर काम शुरू हुआ. तकनीकी संस्थानों में अव्वल आइआइटी ने भी इस दिशा में हाथ बढ़ाया. 2009 में अपने स्थापना समय से ही पटना आइआइटी ने इस पर काम शुरू किया. आज स्थिति यह है कि सौर ऊर्जा के जरिये पटना आइआइटी न सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर बिहार सरकार को भी बिजली सप्लाई करता है. आइआइटी पटना परिसर के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पॉर्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआइ) भवन में 10 किलोवाट क्षमता का एक सोलर पैनल 2010 में लगा था. इसकी कुल लागत तब 32 लाख रुपये थी.

मौजूदा वक्त में सोलर प्लेट सस्ती हुई है. इसी क्षमता वाले पैनल के सेटअप में अब 15-18 लाख रुपये का खर्च आयेगा. संस्थान को सौर ऊर्जा से रोशन करने की पहल इलेक्ट्रिकल विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ रंजन बेहरा ने की थी. इस काम में विभाग के स्टूडेंट ने भी सहयोग किया. डॉ बेहरा ने बताया कि करीब दो साल तक कड़ी शोध में यह बात आयी कि सोलर पैनल को भवन की छत पर किस कोण और दिशा में लगाया जाये. डॉ बेहरा के मुताबिक यह एक चुनौती थी, क्योंकि सोलर पैनल को छत पर आने वाली तेज हवा के झोकों से बचाना था. दूसरा सोलर पैनल को ऐसे कोण में सेट करना था ताकि पैनल को हर मौसम में बराबर धूप मिलती रहे. आमतौर पर सोलर पैनल को लगाने में दिशा, हवा और कोण जैसी चीजों पर शोध गायब रहता है. इसलिए परिणाम बेहतर नहीं आते हैं. डॉ बेहरा कहते हैं, सोलर प्लेट कभी खराब नहीं होते.

बीच से टूट जाने पर भी सोलर प्लेट खराब नहीं होता, हां यह जरूर है कि सोलर प्लेट से पैदा होने वाले करंट और वोल्टेज में अंतर या कमी आ जाती है. इससे बेहतर परिणाम नहीं मिलते. संस्थान में लगे सोलर पैनल से बेहतर करंट और वोल्टेज मिल सके, इसलिए बैटरी की सीरीज पर भी विशेष ध्यान दिया गया है.

अमूमन सोलर प्लेट के साथ एसिड बैटरी का इस्तेमाल होता है, लेकिन संस्थान में सोलर पैनल को जेलयुक्त बैटरी से जोड़ा गया है. कुल 40 बैटरी की सीरीज लगायी गयी है. जेल बैटरी लगाने के पीछे मकसद यह है कि जेल युक्त बैटरी की जिंदगी एसिड बैटरी की तुलना में ज्यादा होती है. इसके रखरखाव पर भी झंझट नहीं है. अब कई भारतीय कंपनियों ने भी जेल युक्त बैटरी बेचना शुरू कर दी है. एक कंट्रोल रूम भी है. इस कंट्रोल रूम से अतिरिक्त ऊर्जा संचित कर बिहार सरकार के ट्रांसफर्मर (ग्रिड सिस्टम) को भेजी जाती है. अब तक संस्थान 25 हजार यूनिट से ज्यादा बिजली बिहार सरकार को सप्लाई कर चुका है.

संस्थान में बन रहा सस्ता सोलर लालटेन

पटना, आइआइटी सौर ऊर्जा से संबंधित कई ऐसे उत्पाद पर भी काम कर रहा है, जिससे भविष्य में कम लागत में सौर ऊर्जा के यंत्रों का लाभ मिल सके. इन दिनों डॉ बेहरा और इलेक्ट्रिकल विभाग के विद्यार्थी एक लालटेन पर काम कर रहे हैं. यह सौर ऊर्जा से संचालित होगा. 4.5 एंपियर की बैटरी से लैस इस लालटेन को 10 घंटे चार्ज करना पड़ेगा. फुल चार्जिंग के बाद 10 दिन तक चलेगी. 10 वॉट के इस लालटेन में एलइडी लाइट लगायी गयी है. एलइडी लाइट कम ऊर्जा खपत करती है. साथ ही रोशनी बढ़िया देती है. बताया कि इस लालटेन में सिंपल सर्किट का प्रयोग किया जा रहा है ताकि किसी तरह की परेशानी होने पर कोई भी इसे आसानी से ठीक कर सके. लालटेन के साथ एक सोलर पैनल भी जुड़ा है. डॉ बेहरा ने बताया कि इस तरह का सोलर लालटेन बाजार में 3000 रुपये का है. लालटेन पर जब काम पूरा हो जाएगा तो यह मौजूदा कीमत से ठीक आधी कीमत पर उपलब्ध होगा.

पवन ऊर्जा में भी संभावना

कैंपस के पास एक पवन चक्की लगायी गयी थी. मौजूदा वक्त में वह काम नहीं कर रही है. डॉ रंजन बेहरा ने बताया कि पवन ऊर्जा की संभावना है, लेकिन बिहार में किसी भी पवन चक्की को बहुत ऊंचाई पर लगाना होगा क्योंकि यहां हवा सभी दिशा से आती है.

सरकार मजबूत करे संवाद

डॉ बेहरा कहते हैं बिहार में सौर ऊर्जा एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है. इसमें नित्य शोध हो रहे हैं. सरकार को और शोध कराना चाहिए. बिहार रेन्यूबल एनर्जी एजेंसी से बहुत पहले एक चिट्ठी संस्थान को आयी थी, जिसमें सूबे में ऊर्जा समाधान पर संस्थान से विचार मांगे गये थे. इसके बाद एजेंसी से कोई संवाद संस्थान का नहीं हुआ है. हालांकि पिछले साल बिहार सरकार ने सिचाई के लिए सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित कराने को लेकर संस्थान से सहयोग की बात कही थी.

(रिपोर्ट 16वीं सीएसइ फैलोशिप प्रोग्राम के तहत प्रकाशित.)

विधानमंडल में आज

विधानसभा

- कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे से
- अल्पसूचित व तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर

ध्यानाकर्षण सूचनाएं
- गोपालगंज जिले के बाढ़पीड़ित परिवारों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने व विस्थापितों को पुनर्वासित कराने के संबंध में
- मधुबनी जिला के छात्रों को प्रवेशिकोत्तर तकनीकी छात्रवृत्ति के तहत प्रोत्साहन के लिए राशि उपलब्ध कराने के संबंध में
- कामेश्वर प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता, शहरी विकास अभिकरण गया पर कार्रवाई के संबंध में
- उत्तराखंड त्रासदी के मृतकों की सूची जारी करने व मुआवजा राशि के भुगतान के संबंध में

राजकीय विधेयक
- बोधगया मंदिर (संशोधन) विधेयक 2013
- बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2013
- पटना विश्वविद्यालय (संशोधन)

विधेयक 2013
- नालंदा खुला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2013

विधान परिषद
- बैठक 10.00 बजे से
- विशेष वाद-विवाद व सरकार का उत्तर
- सारण जिले में धर्मासती नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में विषाक्त मध्याह्न भोजन से हुई मौत एवं उससे उत्पन्न स्थिति पर विशेष वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर.
- प्रश्नोत्तर.

ध्यानाकर्षण
- जयप्रकाश विवि, छपरा अंतर्गत एसएमडी डिग्री कालेज मठिया, नेचुआ जलालपुर, गोपालगंज में अनियमितता के संबंध में.
- मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की भौतिक उपलब्धि के संबंध में.
- हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के अंतर्गत सभी गैर तकनीकी योग्यताधारी पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के पदस्थापन के संबंध में.